दैनिक समाचार पत्र

जीत समाचार

जीत सच्ची खबर की

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश

अनमोल वचन

"यदि संसार में कहीं कोई पाप है तो वह है दुर्बलता। हमें हर प्रकार की कमजोरी या दुर्बलता को दूर करना चाहिए। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु के समान है।"

वर्ष : 13 अंक : 189 मूल्य : 5 रू पृष्ठ : 8

वीरवार
28 मई 2026

RNI NO : PUNHIN/2013/60106 www.zeetsamachar.com

सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा

नई दिल्ली (एजेंसी)। सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया, जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि जब कानून स्वयं किसी भी समय, दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर और चुनाव आयोग द्वारा उचित समझे जाने वाले तरीके से विशेष पुनरीक्षण को अधिकृत करता है, तो विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर-तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए यह नही कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है।

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एसआईआर द्वारा प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के संवैधानिक लक्ष्य से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। न्यायालय ने कहा कि ऐसे चुनाव केवल मतदान की प्रक्रिया पर ही निर्भर नहीं करते, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव रखने वाली मतदाता सूचियों की सत्यनिष्ठा, सटीकता और विश्वसनीयता पर मौलिक रूप से निर्भर करते हैं।

न्यायालय ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा दर्ज किए गए कारण स्पष्ट रूप से उस मूलभूत सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के उद्देश्य से थे। इनमें अंतिम गहन पुनरीक्षण के बाद चार दशकों से अधिक का समय बीत जाना, वर्षों से बड़े पैमाने पर नामों का जुड़ना और हटना और तीव्र शहरीकरण और प्रवासन के कारण मतदाता सूचियों में दोहराव और अशुद्धियों की संभावना शामिल है।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है।

संक्षिप्त न्यूज

राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 7.72 लाख से अधिक हेल्थ कार्ड बनाए गए

नई दिल्ली (एजेंसी)। राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अब तक 7 लाख 72 हजार से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड बनाए जा चुके हैं। इनमें करीब 2 लाख 90 हजार कार्ड वय वंदना योजना के अंतर्गत जारी किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को 10 लाख रूपये तक का नकदी रहित स्वास्थ्य कवरेज मिल रहा है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 5 लाख और दिल्ली सरकार की ओर से अतिरिक्त 5 लाख रूपये की राशि शामिल है। इसके माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों और पात्र परिवारों को स्वास्थ्य सेवा कवरेज का लाभ मिल रहा है। दिल्ली सरकार के अनुसार, इसके तहत अब तक 46 हजार 900 से अधिक मरीजों का इलाज किया जा चुका है। उपचार में अब तक 86 करोड़ 22 लाख रूपये से अधिक के क्लेम का निपटारा हुआ है। योजना के तहत राजधानी के 233 अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है, जिनमें 181 निजी और 52 सरकारी अस्पताल शामिल हैं। वहीं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने हीटवेव को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। लोक नायक अस्पताल में लू से प्रभावित मरीजों के लिए 14 विशेष बिस्तर और 70 बिस्तर का डिजास्टर वार्ड तैयार किया गया है। अस्पतालों में ओआरएस, कूलिंग पैड और आपात सेवाओं की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य हर पात्र नागरिक तक सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है।

सीबीआई ने नीट यूजी-2026 पेपर लीक मामले में तीन और लोगों को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी-2026 पेपर लीक मामले में आज तीन और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ब्यूरो के प्रवक्ता ने कहा कि जांच एजेंसी ने इस मामले में अब तक 49 स्थानों पर छापेमार कर कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लेपटॉप और मोबाइल फोन बरामद किये हैं।

असम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया

असम (एजेंसी) असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है।

इसका उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप से संबंधित मामलों में राज्य के सभी निवासियों के लिए एक समान नागरिक कानूनी ढांचा स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक प्रथाओं को संरक्षित रखने के लिए विधेयक अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखता है। विधेयक में धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों को एक समान ढांचे में रखने की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करना है।

विधेयक पारित होने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि अब यह विधेयक राज्यपाल को भेजा जाएगा। उसके बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही असम में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी।

गुजरात आतंकवाद-विरोधी दस्ते और तटरक्षक बल ने कच्छ तट से 1100 करोड़ रूपये से अधिक के मादक पदार्थ जब्त किए

गुजरात(ब्यूरो)। गुजरात आतंकवाद-विरोधी दस्ते और तटरक्षक बल ने आज एक संयुक्त कार्रवाई में गुजरात के कच्छ जिले के समुद्र तट से 1100 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य के अवैध मादक पदार्थों के 115 पैकेट जब्त किए हैं। ये मादक पदार्थ कच्छ के मुंद्रा बंदरगाह की ओर जा रहे एक जहाज से बरामद किए गए हैं। इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है।

आईएएस 2024 बैच में लगभग 41: महिला अधिकारियों का होना भारत में व्यापक सामाजिक परिवर्तन को दर्शाता है: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह

नई दिल्ली। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2024 बैच में लगभग 41 प्रतिशत महिला अधिकारियों का होना भारत में व्यापक सामाजिक परिवर्तन को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं, उच्च शिक्षा और पेशेवर क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी अवसरों और पहुंच के तेजी से लोकतांत्रिक होने का परिचायक है। आज नई दिल्ली में 2024 बैच के आईएएस अधिकारी प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत में श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज शासन में तकनीकी समझ और अंतर्विषयक सोच की आवश्यकता बढ़ती जा रही है।

उन्होंने अधिकारियों से मिशन कर्मयोगी जैसे प्लेटफार्मों का समुचित उपयोग करने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सार्वजनिक संचार सहित उभरते क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को लगातार बढाने का आग्रह किया।

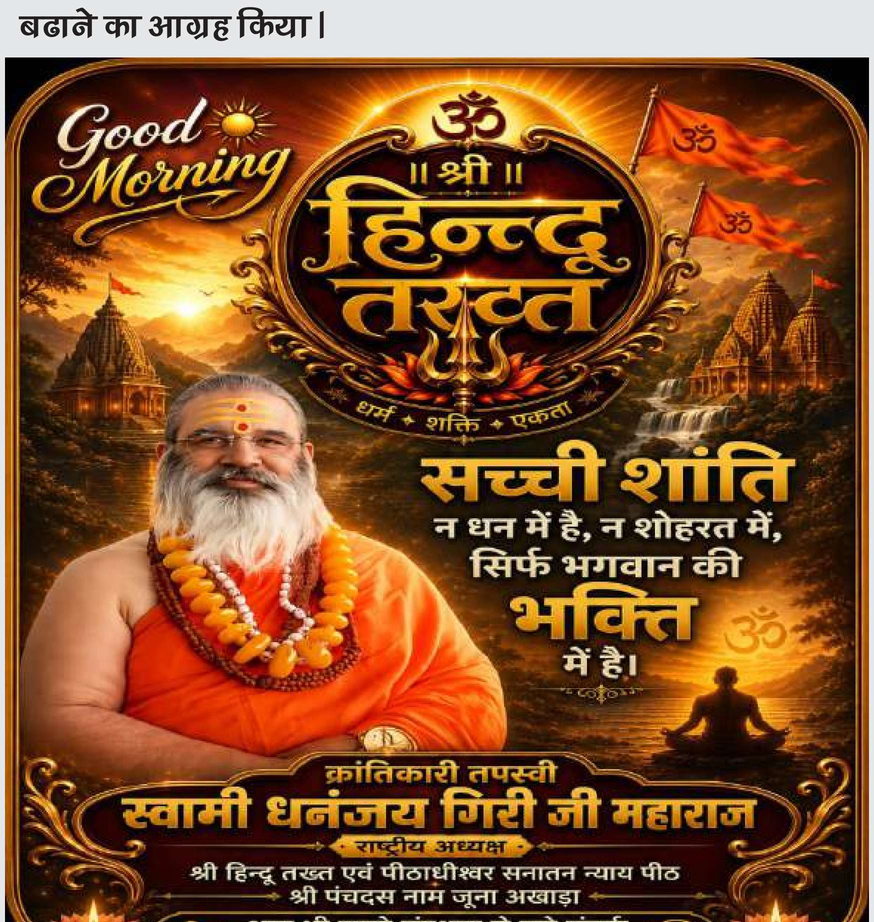

रूसी बैंक कर्मचारी यूक्रेनी ड्रोन हमलों के खिलाफ लड़ाई में हो सकते हैं शामिल

रूस (एजेंसी)। रूस के संसद के निचले सदन द्वारा अनुमोदित एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत रूसी बैंक कर्मचारी यूक्रेनी ड्रोन हमलों के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो सकते हैं। कल पारित मसौदा विधेयक के अनुसार, बैंक अपने परिसरों में इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम स्थापित करने का खर्च वहन करेंगे, जबकि चयनित कर्मचारी आने वाले ड्रोनों को मार गिराएंगे। चूंकि लगभग हर शहर में बैंक हैं, इसलिए हवाई सुरक्षा में उनकी भागीदारी रूस की सुरक्षा को बढ़ाने में मदद कर सकती है।

यह विधेयक पहली बार पिछले अगस्त में प्रस्तुत किया गया था और बाद में इसका दायरा बढ़ाया गया। इसे अभी भी ऊपरी सदन, फेडरेशन काउंसिल द्वारा अनुमोदित किया जाना है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है, जिसके बाद ही यह लागू होगा। इस योजना में रूस का केंद्रीय बैंक और अन्य शीर्ष संस्थान शामिल हैं, जिनमें बहुसंख्यक सरकारी स्वामित्व वाला स्बरबैंक भी शामिल है।

एयर इंडिया की फ्लाइट-182 बम विस्फोट के पीड़ितों को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने श्रद्धांजलि अर्पित की

कनाडा (एजेंसी)। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कनाडा के हंबर बे पार्क के कनिष्क स्मारक में एयर इंडिया की फ्लाइट-182 बम विस्फोट के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि यह हवाई हमला विमानन इतिहास में आतंकवाद की सबसे दुखद घटनाओं में से एक है। उन्होंने कई पीड़ितों के परिवारों से भी मुलाकात की। गोयल ने कहा कि भारत और कनाडा यह सुनिश्चित करने के लिए सहयोग कर रहे हैं कि ऐसी त्रासदी फिर कभी न दोहराई जाए।

रूस के वैज्ञानिकों ने इबोला वायरस के सबसे नए स्ट्रेन के खिलाफ नई वैक्सीन तैयार की

रूस(एजेंसी)। दक्षिण अफ्रीका में रूसी दूतावास ने कहा है कि रूस के वैज्ञानिकों ने इबोला वायरस के सबसे नए स्ट्रेन के खिलाफ एक नई वैक्सीन तैयार की है। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराश्को ने इस उपलब्धि की घोषणा की। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह वैक्सीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो में हाल ही में फैले दुर्लभ 'बुंडीबुग्यो' स्ट्रेन के खिलाफ भी असरदार हो सकती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस महीने की 17 तारीख को 'अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों' के तहत, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को 'वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल' घोषित कर दिया।

इधर देश में हाल ही में, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने भी, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे 'अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल' घोषित किए जाने के बाद, एयरलाइनों के लिए एक 'मानक संचालन प्रक्रिया' जारी की है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कहा कि युगांडा और कांगो से आने-जाने वाली उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइनों के लिए यह अनिवार्य है कि वे यात्रियों के विमान से उतरने से पहले, उनसे 'स्व-घोषणा पत्र' अनिवार्य रूप से भरवाएं।

अफ्रीका सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन' ने भी इस प्रकोप को पूरे महाद्वीप के लिए एक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी देशों को सलाह दी है कि वे प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों की जांच (स्क्रीनिंग) को और अधिक सख्त करें, और उन जगहों की यात्रा करने से बचें जहां 'बुंडीबुग्यो' वायरस पाया गया है। दक्षिण सूडान सहित, कांगो के पड़ोसी देशों में इस संक्रमण के फैलने का खतरा सबसे अधिक माना जा रहा है। इबोला एक गंभीर वायरल बीमारी है, जिसमें मृत्यु दर काफी अधिक होती है। फिलहाल, 'बुंडीबुग्यो' स्ट्रेन के लिए विशेष रूप से तैयार की गई कोई भी आधिकारिक रूप से स्वीकृत वैक्सीन या उपचार उपलब्ध नहीं है।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 78 हजार तक की सब्सिडी

डीसी डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना के तहत अधिकतम 78 हजार रूपये की सब्सिडी दी जा रही है।

जीत समाचार हरियाणा (ब्यूरों)। डीसी डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना के तहत अधिकतम 78 हजार रूपये की सब्सिडी दी जा रही है।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना के द्वारा समाज के गरीब वर्ग की ऊर्जा संबंधित जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। इस योजना से गरीब परिवारों का ऊर्जा खर्च लगभग खत्म हो जाएगा। अगर खपत से ज्यादा बिजली का उत्पादन सोलर पैनल द्वारा किया जाता है तो वह बिजली के खाते में जाएगा जिसका भुगतान सरकार द्वारा उक्त मकान मालिक को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह योजना गरीब परिवारों के सशक्तिकरण में लाभकारी होगी। योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और वे आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे। इस योजना से सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम होगा और स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों को अपनाने में मदद मिलेगी।

डीसी ने बताया कि केंद्र सरकार की सब्सिडी के अतिरिक्त हरियाणा के एक लाख गरीब परिवारों को सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 50 हजार रूपये की सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी। ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रूपये से कम है तथा एक लाख 80 हजार रूपये से लेकर 3 लाख रूपये तक की वार्षिक आय के लाभार्थी व वार्षिक अधिकतम 2400 यूनिट की खपत वाले उपभोक्ता हैं, वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। पहले 2 किलोवाट तक 30 हजार रूपये प्रति किलोवाट के हिसाब से 60 हजार रूपये तक सब्सिडी दी जाएगी। अगले एक किलोवाट यानी की 2 से 3 किलोवाट तक रूफ टॉप सिस्टम लगवाने पर 18 हजार रूपये की सब्सिडी दी जा रही है। इस तरह से अधिकतम 78 हजार रूपये की सब्सिडी दी जा रही है।

खेल

आईपीएलः क्वालीफायर मैच में गुजरात टाइटन्स को हरा फाइनल में पहुंची रॉयल चौलेंजर्स बेंगलुरू

आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चौलेंजर्स बेंगलुरू ने कल पहले क्वालीफायर मैच में गुजरात टाइटन्स को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटन्स 162 रन पर ही सिमट गई। रजत पाटीदार को नाबाद 93 रन की पारी के लिये प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

प्रतियोगिता में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। मैच शाम साढ़े सात बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालीफायर में गुजरात टाइटन्स से भिड़ेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।

Samuh Samaj Sangathan (Regd.)
2007 to Update
अभी नहीं तो कभी नहीं
मानवता की रक्षा एवं सुरक्षित रखने का मौका।
सच्चाई से देश सेवा।
समूह समाज संगठन 2007 से जरूरतमंद लोगों की हमेशा से मदद करता आया है। यह तभी संभव होता है जब आप सभी लोग हमारे संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते है। आज की मुसीबत के समय में राशन और डेली जरूरत की सामग्री मस्क, सेनिटाइजर आदि इकठ्ठा करना जितना मुश्किल है। उससे मुश्किल इस सामग्री को बटना और लोगो तक पहुंचाना है।
किसी को हमारे संगठन के होते घबराने की जरूरत नहीं है हमारे संगठन के वॉलंटियर्स आपकी सेवा में हाजिर है। सम्पर्क करें।
9803025111,9872081907,7696420000,9872177784,8427566893

ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ ਸੰਗਠਨ (ਸਸਸ) ਰਜਿ.
SSS
ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ
ISO ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਤ੍ਰਾਲੀ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ
ਵੇਸਟ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਿਸਾਇਕਲਿੰਗ
ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਉ
ਵਾਰਡ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ
ਸੰਪਰਕ : 85679-57745, 90410-90470

पद्म पुरस्कार-2027 के नामांकन के लिए आवेदन आमंत्रितः डीसी डॉ. आनंद कुमार शर्मा

जीत समाचार हरियाणा(ब्यूरों)। डीसी डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि गणतंत्र दिवस 2027 पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकनधसिफारिशों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पुरस्कारों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल (https://awards-gov-in/) पर 31 जुलाई, 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किए जा सकते हैं। इन पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण व पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं।

डीसी डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि नामांकन करने वाले व्यक्ति अधिकतम 800 शब्द का एक व्याख्यात्मक प्रशस्ति-पत्र जिसमें अनुशंसित व्यक्ति की संबंधित क्षेत्रधविषय में विशिष्ट और अन्य उपलब्धियोंध्सेवाओं का स्पष्ट उल्लेख किया गया हो, प्रस्तुत करें।

उन्होंने बताया कि पद्म पुरस्कार, अर्थात् पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से हैं। वर्ष 1954 में स्थापित इन पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। यह पुरस्कार कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सार्वजनिक कार्य, नागरिक सेवाओं, व्यापार और उद्योग जैसे सभी क्षेत्रोंधविषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवाओं के लिए उत्कृष्ट-कार्य को मान्यता प्रदान करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। जाति, व्यवसाय, पद या लैंगिक भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। डॉक्टर और वैज्ञानिकों को छोड़कर सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी पद्म पुरस्कार के लिए पात्र नहीं हैं। इस संबंध में और अधिक विवरण वेबसाइट पदमा अवार्ड.जीओवी.इन पर उपलब्ध है।

दैनिक समाचार पत्र
जीत समाचार
जीत सच्ची खबर की
www.zeetsamachar.com

वैश्विक संकट और महंगाई के मुख्य प्रभाव

ऊर्जा संकट और पेट्रोल-डीजलः

होर्मुज स्ट्रेट में तनाव के कारण कच्चे तेल के वैश्विक व्यापार में भारी उतार-चढ़ाव आया है। कई देश ऊर्जा उपलब्धता के संकट से जूझ रहे हैं। हालाँकि, भारत सरकार की नीतियों और तेल विपणन कंपनियों द्वारा भार वहन करने के कारण भारत में खुदरा पेट्रोल-डीजल की कीमतों (जैसे पिछले 4 महीनों में केवल 3.2ः वृद्धि) को अन्य देशों (जैसे 50प्रतिशत-90प्रतिशत तक की भारी बढ़ोतरी वाले देशों) की तुलना में स्थिर रखा गया है।

खाद्य और उर्वरक की महंगाई :

रूस-यूक्रेन संघर्ष और वैश्विक तनाव के कारण खाद व कच्चे माल की कीमतों में उछाल आया है। इसका असर भारत की खाद्य आपूर्ति श्रृंखला पर भी पड़ा थें।

गरीबी पर असरः

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक तनावों के कारण विकासशील देशों में गरीबी का स्तर बढ़ सकता है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं।

स्थानीय प्रभावः

हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी अंतरराष्ट्रीय संकटों के कारण बढ़ रही महंगाई (पेट्रोल-डीजल, गैस और आवश्यक वस्तुओं के दाम) को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं, क्योंकि परिवहन और निर्माण लागत में वृद्धि होती है

- कमल पवार

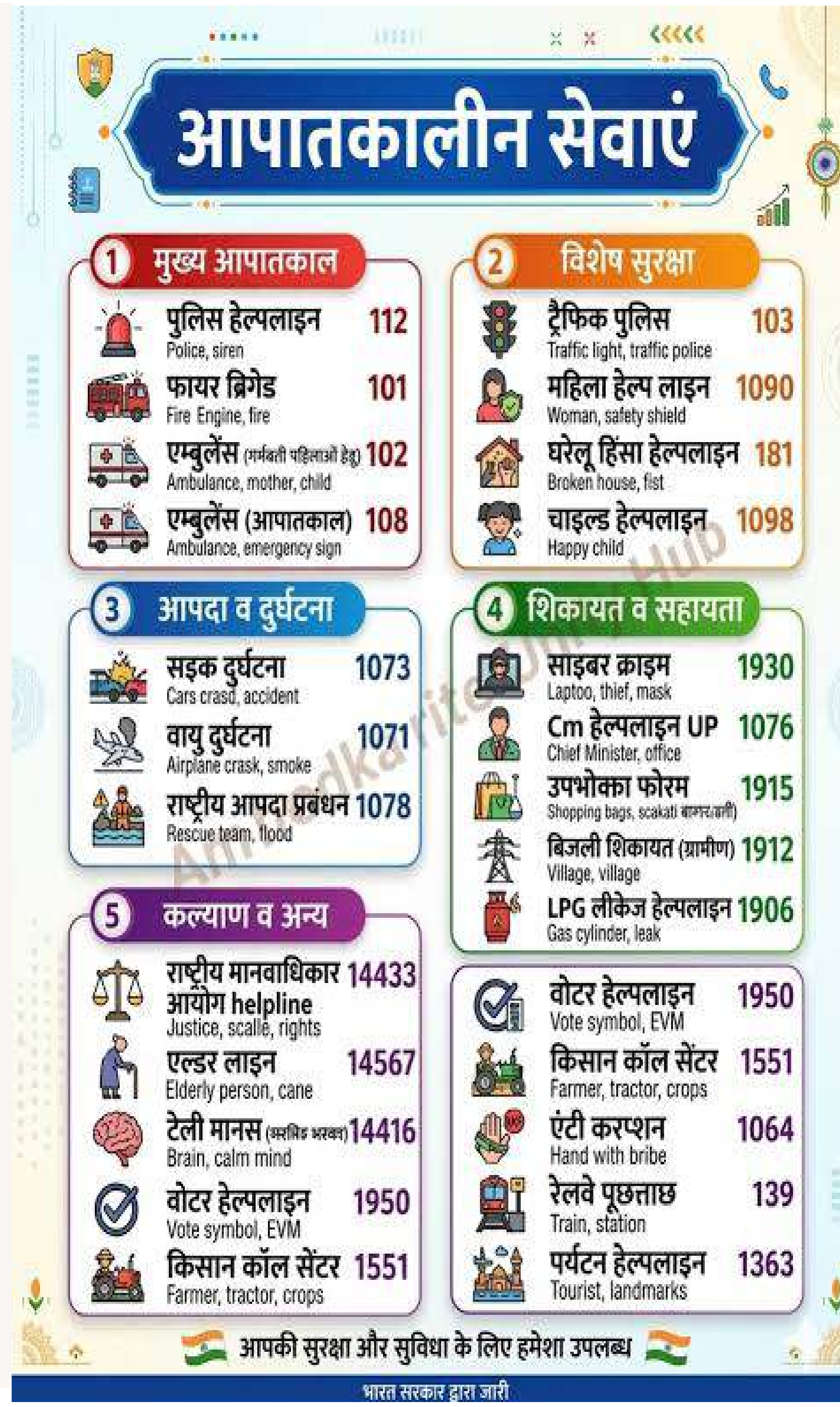

जीत क्लासीफाइड

अपना क्लासिफाईड/ डिस्पले विज्ञापन
अपना नाम परिवर्तन, मकान,
शादी, जन्मदिन आदि के लिए सम्पर्क करे।
9803025111, 8878400009

जीत समाचार TV
जीत सच्ची खबर की
जीत समाचार को हर जिले, शहर आदि से रिपोर्ट की आवश्यकता है। यदि आप में है दम तो मौका देगे हम!
जीत समाचार आपकी तीसरी आँख बन कर आपका मार्गदर्शन करेगा। आप के शहर मे कोई ऐसी खबर हो तो आप हमारी अखबार व टीवी में दिखाना चाहते है तो सम्पर्क करे।
9041090470

दैनिक समाचार पत्र
जीत समाचार
जीत सच्ची खबर की
मुद्रक, प्रकाशक व सम्पादक : कमल पवार द्वारा 11368, पवित्र नगर, वालिया कालोनी हैबोवाल कलां, लुधियाना से प्रकाशित एंव जीत लुधियाना प्रिंटर्स हैबोवाल लुधियाना से मुद्रित।
सम्पादक : कमल पवार इस अंक मे प्रकाशित एंव समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादक हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी तथा उत्पन्न समस्त विवाद लुधियाना न्यायालय के अधीन होंगे।
R.N.I NO. PUN/HIN/2013/60106
Contact us :- +91-98030-25111.

तेल की कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी' : विधायक कुलवंत सिंह सिद्धू

धान सीजन में किसानों पर पड़ेगी मार' : डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ेगा

जीत समाचार लुधियाना (यादविंदर) ।विधानसभा हलका आत्म नगर से विधायक कुलवंत सिंह सिद्धू ने सोमवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी पर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि तेल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी को बुरी तरह प्रभावित किया है और घरेलू बजट को हिला कर रख दिया है।

महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी : सिद्धू प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विधायक सिद्धू ने आरोप लगाया कि महंगाई ने जनता की "कमर तोड़" दी है। लोग रोजाना के खर्चों का प्रबंधन करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुश्किल समय में राहत देने की बजाय, केंद्र सरकार ने आम नागरिकों को अकेला छोड़ दिया है। आर्थिक तंगी के समय में लोगों के साथ खड़ा होना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन मोदी के नेतृत्व वाली सरकार महंगाई को कंट्रोल करने और जनता को राहत देने में पूरी तरह फेल रही है', सिद्धू ने कहा।

धान के सीजन में किसानों की जेब पर भार : विधायक ने आने वाले धान के सीजन पर चिंता जताते हुए कहा कि किसानों को अब ट्रैक्टर, ट्यूबवेल और दूसरी खेतीबाड़ी मशीनरी के लिए डीजल पर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा ।सिद्धू ने चेतावनी दी कि डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से ट्रांसपोर्ट लागत भी बढ़ेगी, जिससे सब्जियां, फल, अनाज और दूसरी जरूरी चीजों की कीमतें और बढ़ जाएंगी।'किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग के परिवार और दिहाड़ीदार तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे', उन्होंने कहा।

कॉर्पोरेट के लिए मुनाफा, जनता के लिए दर्द : पवन दीवान ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में तत्काल कटौती की मांग की

रिकॉर्ड तेल मुनाफों के बावजूद लगातार ईंधन महंगा करने की कांग्रेस ने की निंदा

जीत समाचार लुधियाना (यादविंदर)। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बार-बार की जा रही बढ़ोतरी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए जिला कांग्रेस कमेटी लुधियाना (शहरी) के पूर्व अध्यक्ष तथा पंजाब लार्ज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड के पूर्व चेयरमैन पवन दीवान ने कहा है कि मात्र 10 दिनों के भीतर लगातार चार बार कीमतें बढ़ाकर प्रति लीटर लगभग 7.5 रुपये की कुल वृद्धि कर दी गई है, जिससे देशभर के लोग हैरान और परेशान हैं। उन्होंने कहा कि इसके कारण परिवारों के लिए अपने घरेलू खर्चों का प्रबंधन करना और भी कठिन हो गया है।

यहां जारी एक तीखे बयान में, दीवान ने इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि जब सरकारी तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) भारी मुनाफा कमा रही हैं, उसी समय ईंधन की कीमतों में लगातार और कम अंतराल पर वृद्धि की जा रही है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान ओएमसी ने कुल 77,280.65 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 130 प्रतिशत अधिक है। इसके बावजूद उपभोक्ताओं पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बार-बार बढ़ोतरी का बोझ डाला जा रहा है। दीवान ने कहा कि इतने बड़े मुनाफे के मद्देनजर सरकार की मूल्य निर्धारण नीति का बचाव करना असंभव हो जाता है। उन्होंने कहा कि हर कुछ दिनों बाद की जा रही अनुचित मूल्य वृद्धि से आम परिवारों और छोटे कारोबारियों पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा है।

मोदी सरकार पर जनकल्याण की बजाय कॉर्पोरेट मुनाफे को प्राथमिकता देने का आरोप लगाते हुए, दीवान ने कहा कि यह बेहद आश्चर्यजनक है कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने के बावजूद देश में ईंधन की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जब कच्चे तेल के दाम घटते हैं तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी कम होनी चाहिए, लेकिन इस सरकार के कार्यकाल में स्थिति बिल्कुल उलट है। दीवान ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की छिपी मूल्य निर्धारण प्रणाली तेल कंपनियों के हितों की रक्षा का माध्यम बन गई है, जबकि आम नागरिकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।

पारदर्शी मूल्य निर्धारण और जवाबदेही की मांग करते हुए, दीवान ने सरकार से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तत्काल कटौती करने की मांग की, ताकि परिवारों, दैनिक यात्रियों और छोटे व्यवसायों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि राहत में अब और देरी नहीं होनी चाहिए। जनता शोषण नहीं, बल्कि न्याय की हकदार है।

एडीसी ने घर-घर जाकर गिनती के काम के दौरान जनगणना कर्मचारियों को आने वाली चुनौतियों की समीक्षा की

जीत समाचार लुधियाना। अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला जनगणना अधिकारी पूनम सिंह ने बुधवार को जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत लुधियाना पश्चिम तहसील में तैनात गणनाकारों और पर्यवेक्षकों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस चरण में घर-घर जाकर गिनती (हाउस लिस्टिंग) और आवास जनगणना का काम शामिल है।

बैठक के दौरान जिला जनगणना समन्वयक आलोक कुमार, मास्टर ट्रेनर उपमा कौल, जनगणना कर्मचारी, लुधियाना पश्चिम के तहसीलदार और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

बैठक के दौरान, एडीसी ने चल रही जमीनी गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की और जनगणना के काम के दौरान गणनाकारों और पर्यवेक्षकों को आ रही विभिन्न तकनीकी, प्रशासनिक और परिचालन चुनौतियों पर चर्चा की। उन्होंने जनगणना के काम को सुचारू, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए जरूरी मार्गदर्शन और निर्देश दिए।

सौंपे गए कार्यों की सटीकता और समय पर पूरा होने के महत्व पर जोर देते हुए, पूनम सिंह ने जमीनी कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे घर-घर जाकर गिनती का काम करते समय जनगणना के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें। उन्होंने अधिकारियों से यह भी आग्रह किया कि वे गुणवत्तापूर्ण डेटा संग्रह सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर तालमेल बनाए रखें। उन्होंने पर्यवेक्षकों को आगे निर्देश दिया कि वे गणनाकारों के काम की नियमित रूप से निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि सर्वेक्षण प्रक्रिया के दौरान कोई भी घर छूट न जाए।

जनता के सहयोग के महत्व पर जोर देते हुए, एडीसी ने जमीनी कर्मचारियों से कहा कि वे निवासियों के साथ बातचीत करते समय विनम्र व्यवहार रखें और जनगणना गतिविधियों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाएं।

एडीसी ने यह भी बताया कि जनगणना के दौरान एकत्र किया गया डेटा नीति निर्माण, कल्याणकारी योजनाओं की योजना बनाने, बुनियादी ढांचे के विकास और सरकारी संसाधनों के आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए सटीक जनगणना डेटा जरूरी है।

अधिकारियों ने बैठक के दौरान बताया कि जनगणना 2027 के जमीनी कार्यों के लिए पूरे लुधियाना जिले में लगभग 10,000 गणनाकार और लगभग 1,600 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं।

एडीसी पूनम सिंह ने पूरे जिले में विश्वसनीय और व्यापक डेटा संग्रह सुनिश्चित करने के लिए जनगणना के काम को कुशलतापूर्वक और व्यवस्थित रूप से संचालित करने की प्रशासन की प्रतिबद्धता को दोहराया।

ग्राम पंचायत चुनाव

ग्राम पंचायत चुनाव में राजीव सिंह की शानदार जीत

जीत समाचार पंचरूखी (भतर सिंह)। ग्राम पंचायत टटेहल चुनाव के घोषित परिणामों में एक महत्वपूर्ण उलटफेर देखने को मिला है, जहाँ उप-प्रधान पद के उम्मीदवार राजीव सिंह ने शानदार जीत दर्ज की है। राजीव सिंह को कुल 375 वोट प्राप्त हुए हैं, जिससे उनकी जीत सुनिश्चित हुई। जीत के बाद समर्थकों में भारी उत्साह है। समर्थकों ने राजीव सिंह को फूल-मालाएं पहनाकर और मिठाई खिलाकर बधाई दी। अपनी जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए राजीव सिंह ने ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, 'यह जीत मेरी नहीं, बल्कि ग्राम पंचायत के प्रत्येक नागरिक की जीत है। मैं अपने पंचायत के विकास और जन-कल्याण के लिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करूँगा।'राजीव सिंह ने ग्राम पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी ढांचों के विकास को अपनी प्राथमिकता बताया है। क्षेत्र के निवासियों ने इस जीत पर खुशी जताई है और उम्मीद जताई है कि उनके नेतृत्व में पंचायत एक नई विकास यात्रा की ओर अग्रसर होगी।

नियुक्ति के दिन या इससे पहले ईएसआईसी पोर्टल पर हो कर्मचारियों का पंजीकरण

40 वर्ष से अधिक आयु के सभी कर्मचारियों की वार्षिक स्वास्थ्य जांच भी अनिवार्य

जीत समाचार हमीरपुर(ब्यूरों)। बद्दी स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के क्षेत्रीय कार्यालय के उपनिदेशक (जनसंपर्क) ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020 एवं इसके अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम-2025 के तहत कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआई स्कीम) से संबंधित दो महत्वपूर्ण प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। इन प्रावधानों का उद्देश्य श्रमिकों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करना है।

उन्होंने बताया कि सभी नियोजकों के लिए अब ईएसआई स्कीम के अंतर्गत कर्मचारियों का आधार आधारित पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए, सभी नियोजक अपने प्रत्येक कर्मचारी का ईएसआईसी पोर्टल पर आधार आधारित पंजीकरण नियुक्ति की तिथि से पूर्व अथवा उसी दिन सुनिश्चित करें। पंजीकरण के समय कर्मचारी का आधार विवरण एवं अन्य व्यक्तिगत जानकारी पोर्टल पर अंकित की जाएगी तथा निगम द्वारा बीमित व्यक्ति एवं उसके आश्रित परिवारजनों को आधार से लिंक पहचान पत्र उपलब्ध करवाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सभी नियोजक अपने कर्मचारियों के विवरण का प्रमाणीकरण यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित बायोमैट्रिक, ओटीपी अथवा फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से 30 दिनों के भीतर अवश्य करवाएं। निर्धारित अवधि में प्रमाणीकरण न होने की स्थिति में संबंधित पंजीकरण अमान्य माना जाएगा।

उपनिदेशक ने बताया कि चार नई श्रम संहिताओं लागू होने के बाद 40 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच अब अनिवार्य कर दी गई है। सभी नियोजक ईएसआई स्कीम के अंतर्गत अपने कर्मचारियों को स्वास्थ्य जांच के लिए एक दिन का सवेतन अवकाश प्रदान करें, ताकि वे निर्धारित स्वास्थ्य जांच शिविरों में अपनी जांच करवा सकें। इसमें रक्त जांच, छाती का एक्स-रे, ईसीजी तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा परामर्श शामिल है। यह सुविधा सभी ईएसआईसी एवं ईएसआईएस अस्पतालों में पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है।

ईएसआईसी अस्पताल गांव कत्था, बद्दी और ईएसआईएस अस्पताल परवाणु के अलावा ऊना जिले के कर्मचारियों के लिए ईएसआईएस अस्पताल होशियारपुर में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनके अतिरिक्त काला अंब के ईएसआईसी मॉडल अस्पताल में भी स्वास्थ्य जांच शिविर आरंभ किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि सभी नियोजक अपने क्षेत्र के कर्मचारियों को स्थानीय ईएसआईसी शाखा कार्यालय अथवा स्थानीय सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के समन्वय से चरणबद्ध ढंग में स्वास्थ्य जांच हेतु भेजें।

प्रगतिशील किसान के घर एवं खेतों में पहुंची डीसी गंधर्वा राठौड

निर्माणाधीन राज्य उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का भी किया निरीक्षण

जीत समाचार हमीरपुर (ब्यूरो) ।उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने बुधवार को यहां शहर के साथ लगते दोसड़का क्षेत्र के एक प्रगतिशील किसान परमिंद्र सिंह डडवाल के घर एवं खेतों में जाकर उनके द्वारा की जा रही आधुनिक एवं मल्टीपल फार्मिंग का जायजा लिया।

इस दौरान उपायुक्त ने परमिंद्र सिंह डडवाल द्वारा उगाई गई विभिन्न फसलों की पनीरी, औषधीय पौधों, बहुफसली विधि से लगाए गए अन्य पौधों और विशेषकर, बांस, पुरानी पाइपों एवं अन्य वेस्ट मैटीरियल का सदुपयोग करते हुए इसमें लगाए गए पौधों का अवलोकन किया।

उन्होंने वेस्ट मैटीरियल के भरपूर सदुपयोग और बहुफसली विधि को अपनाने के लिए परमिंद्र सिंह डडवाल की सराहना की। उपायुक्त ने कहा कि परमिंद्र सिंह डडवाल ने खेती में जिस तरह इनोवेशन के साथ नए-नए प्रयोग किए हैं, वह बहुत ही प्रशंसनीय है और उनकी यह पहल अन्य किसानों के लिए प्रेरणदायी साबित हो सकती है। उपायुक्त ने परिमंद्र सिंह डडवाल के 'वेस्ट टू प्लेट' के संकल्प की काफी सराहना की। इस संकल्प के तहत वह वेस्ट मैटीरियल का खेती में उपयोग कर रहे हैं।

इस अवसर पर आतमा परियोजना हमीरपुर के परियोजना निदेशक राकेश धीमान, कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. डीडी शर्मा और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

इसके बाद उपायुक्त ने हथली खड्ड के निकट कृषि विभाग के परिसर में विकसित की जा रही राज्य उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का निरीक्षण किया और इसमें अत्याधुनिक उपकरणों को स्थापित करने के कार्य का जायजा लिया। उन्होंने आने वाले हफ्तों में इस प्रयोगशाला का परिचालन आरंभ करने को लेकर भी कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की।

29 को अपने दस्तावेज लें जिला परिषद और बीडीसी के मतगणना एजेंट

जीत समाचार हमीरपुर । एसडीएम एवं उपमंडल हमीरपुर के निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संजीत सिंह ने उपमंडल के अंतर्गत जिला परिषद और बीडीसी के विभिन्न वार्डों के उम्मीदवारों से अपील की है कि वे 31 मई को होने वाली मतगणना के लिए अपने-अपने मतगणना एजेंटों को अधिकृत कर दें और इनसे संबंधित फार्म एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज 29 मई दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक खंड विकास अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर लें। एसडीएम ने कहा कि निर्धारित अवधि के बाद कोई भी आवेदन या दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा।

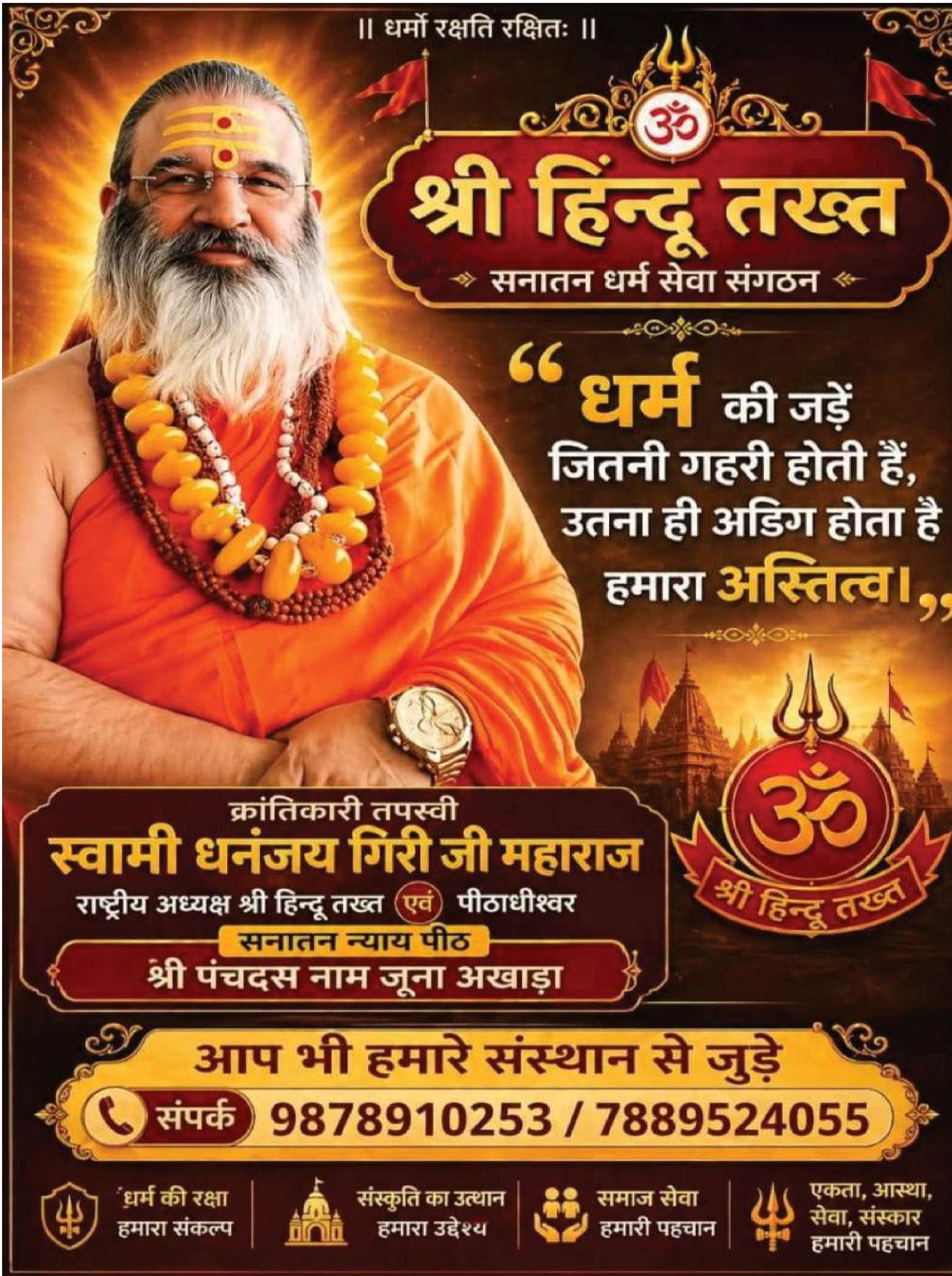
|| धर्मो रक्षति रक्षितः ||
ॐ
श्री हिंन्दू तख्त
सनातन धर्म सेवा संगठन
"धर्म की जड़ें
जितनी गहरी होती हैं,
उतना ही अडिग होता है
हमारा अस्तित्व।"
ॐ
श्री हिन्दू तख्त
क्रांतिकारी तपस्वी
स्वामी धनंजय गिरी जी महाराज
राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हिन्दू तख्त एवं पीठाधीश्वर
सनातन न्याय पीठ
श्री पंचदस नाम जूना अखाड़ा
आप भी हमारे संस्थान से जुड़े
संपर्क 9878910253 / 7889524055
धर्म की रक्षा
हमारा संकल्प
संस्कृति का उत्थान
हमारा उद्देश्य
समाज सेवा
हमारी पहचान
एकता, आस्था,
सेवा, संस्कार
हमारी पहचान